International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 10 Issue 5, September-October, 2022, Impact Factor: 7.326

भरण–पोषणः भारत में घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सामाजिक न्याय की एक पद्धति

प्रो विनोद तिवारी[1], श्रीमति बरखा वर्मा[2]

[1]प्रधानाचार्य एवं एच.ओ.डी., (विधि विभाग) राजीव गाँधी कॉलेज, विधि विभाग, बरकतुल्लाह विशवविधालय भोपाल, मध्यप्रदेश
[2]शोध विद्यार्थी (रिसर्च स्कोलर) विधि विभाग बरकतुल्लाह विशवविधालय भोपाल, मध्यप्रदेश

संक्षेप

एक पीड़ित पत्नी को भरण–पोषण देना किसी और के बिना नागरिक अधिकारों का अनुपात है। यह एक आदमी का महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह अपने महत्वपूर्ण अन्य, बच्चों, अभिभावकों, घनिष्ठ संबंधों आदि के साथ बनाए रखे, क्योंकि वे अपने साथ नहीं रख सकते। यह पत्र बेशर्मी और हताशा को रोकने और महिलाओं और बच्चों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भरण–पोषण के उद्देश्य पर चर्चा करता है। भारत में हिंदू महिलाओं से संबंधित भरण–पोषण विधि को दो प्रकारों में व्यवस्थित किया जा सकता है, यह पेपर अंतरिम भरण–पोषण के अधिकार पर प्रकाश डालता है, पेपर के इस हिस्से में विधवा के लिए भरण–पोषण पेंडेंट लाइट भरण–पोषण शामिल है। मुख्य प्रकार अलगाव, या किसी अन्य वैवाहिक इलाज के बाद भरण–पोषण की कल्पना करता है, उदाहरण के लिए, कागज के इस भाग में विवाह की अशक्तता, आवश्यक ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में बताती है कि एक महिला को वैकल्पिक आवास / अलग आवास का अधिकार कब मिल सकता है। प्रिंसिपल क्लास में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत और दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 के तहत पति या पत्नी, माता–पिता और बच्चों के लिए द्वितीय श्रेणी में भरण–पोषण का दावा किया जा सकता है। और हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956। इस पत्र में, हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम 1956 के तहत एक पति या पत्नी, विधवा और वार्ड को बनाए रखने की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए एक प्रयास किया गया है। इसके अलावा, इस पत्र में दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 पर चर्चा की गई है। पी.सी. हिंदू परिवार के शीर्ष की देखरेख करने वाले गहन भरण–पोषण विधि, और कुछ इसी तरह के पर्याप्त इलाज को समायोजित किया गया है। यह हिस्सा भारतीय विधि और उद्देश्य और भरण–पोषण के दायरे पर प्रकाश डालता है और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956 और दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 के तहत भरण–पोषण कानूनों के बीच तुलना पर चर्चा करता है। इस पेपर के अंतिम भाग में निष्कर्ष – सुझाव और निष्कर्ष शामिल हैं। दृ

सूचक :– भरण–पोषण, घरेलू हिंसा, लिंग, विधि आयोग, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956

1. प्रस्तावना

(ए) भरण–पोषण की भारतीय अवधारणा

भरण–पोषण का अधिकार एक अविभाजित परिवार के विचार से आता है, जहाँ ऐसे परिवार के मुखिया को निःसंदेह उस व्यक्ति के साथ भरण–पोषण की आवश्यकता होगी जो उचित जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से स्वायत्त नहीं है और जीवन की आवश्यकताओं में भाग लेने के लिए सुसज्जित है, जिसमें व्यक्ति प्रश्न की समझदारी से सराहना की उम्मीद है। भरण–पोषण का पूरा विचार ऐसे व्यक्ति के जीवन को बोधगम्य और स्वायत्त बनाने से परिचित था। भरण–पोषण एक व्यक्ति का दायित्व है जो वह अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के प्रति देय होता है जिसके द्वारा व्यक्ति और संपत्ति दोनों बंधे होते हैं। भारतीय विधि के तहत, 'भरण–पोषण' शब्द में भोजन, पोशाक और अभयारण्य की योग्यता शामिल है, जो आमतौर पर पति या पत्नी, बच्चों और अभिभावकों के लिए सुलभ होती है। यह नागरिक अधिकारों का एक अनुपात है, जो किसी व्यक्ति के अपने महत्वपूर्ण अन्य, बच्चों और अभिभावकों के साथ बनाए रखने के नियमित दायित्व के परिणामस्वरूप होता है, जब वे अपने साथ नहीं रख सकते। भरण–पोषण न केवल अधिक नाजुक वर्गों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का विषय रहा है। जब कोई, पर्याप्त साधन होने के बावजूद, अपने आश्रितों के भरण–पोषण की उपेक्षा करता है, उस बिंदु पर, ऐसे संबंधित लोग मदद के लिए राज्य पर गिरने के लिए मजबूर होते हैं या संभवतः आम जनता द्वारा तिरस्कार या अस्वीकार किए गए ट्रांसपोर्टर को लेने के लिए मजबूर होते हैं, जो विरोध करता है आम जनता के हित के साथ। इन पंक्तियों के साथ, इसकी पुष्टि में और उन परिणामों को रोकने के लिए जो अक्सर आवश्यकता और हताशा से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, एक अधिकार, जो गोपनीयता कानूनों के तहत दिए गए एक के अनुरूप है, को अतिरिक्त रूप से भारत में आपराधिक क्षेत्राधिकार के तहत सुलभ बनाया गया है। भरण–पोषण का उद्देश्य अभद्रता और हताशा को रोकना और महिलाओं और बच्चों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के तहत भरण–पोषण के लिए सुसज्जित लोग पति या पत्नी, शोक संतप्त बहू, युवा, परिपक्व अभिभावक और आश्रित हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट है। जबकि, मुस्लिम विधि के तहत, लोग पति या पत्नी, छोटे बच्चों, आवश्यक अभिभावकों और अन्य आवश्यक संबंधों को अस्वीकृत डिग्री के भीतर बनाए रखने के हकदार हैं। भरण–पोषण का मुस्लिम विधि व्यक्तिगत मुस्लिम कानूनों और विधि प्रतिष्ठानों पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए, भारतीय बहुमत अधिनियम, 1875, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986। धारा 125 का उद्देश्य , करोड़। पीसी, 1973 लागू होते हैं और व्यक्तिगत विधि की परवाह किए बिना भारत में लोगों को शासित किया जाता है। साथ ही, यह माना जाना चाहिए कि संबंधित सभाओं के व्यक्तिगत कानूनों, हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों के बारे में उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि विवाह बंधन की वैधता को समाप्त करने के लिए समान हैं, यदि कोई हो, (मौजूद है या नहीं) इस प्रकार हो सकता है' उचित विचार से बचाया नहीं जा सकता।

2. हिंदू विधि के तहत भरण–पोषण

मनु और बृहस्पति सहित प्राचीन भारत के कई हिंदू संतों का मूल्यांकन किया गया था कि विशिष्ट लोगों का भरण–पोषण एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। "एक आदमी बाद में परिवार का भोजन और पोशाक दे सकता है। जो (प्रदाता) अपने परिवार को बिना भोजन के छोड़ देता है, वह शुरू से ही शहद का स्वाद ले सकता है, हालांकि, बाद में उसे जहर मिल जाता है।" हिंदू विधि के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्थापित स्कूलों में से एक, मिताक्षरा का कहना है कि "जहां स्वयं अर्जित की गई संपत्ति के अलावा कोई संपत्ति नहीं हो सकती है, मुख्य लोग जिनकी ऐसी संपत्ति से भरण–पोषण बुनियादी है, परिपक्व अभिभावक, पति या पत्नी हैं और नाबालिग युवा।"

हिंदू विधि के तहत भरण–पोषण का उद्देश्य

(अ) शास्त्री हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में इसकी अंतर्निहित नींव को ट्रैक करता है, जिनकी धर्मशास्त्र में छिपी हुई स्थापनाएं हैं। समय के प्रवेश के साथ, विवाह, स्वागत, प्रगति और भरण–पोषण से संबंधित हिंदू विधि के संहिताकरण की आवश्यकता महसूस की गई, और

इस तरह, दो मानक प्रदर्शन

(1) हिंदू विवाह अधिनियम और

(2) हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 घोषित किया गया था।

इसके बावजूद, हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों में तीन मूलभूत स्रोत शामिल हैं, उदाहरण के लिए, (I) इक्विटी, जस्टिस और ग्रेट स्टिल, छोटी आवाज (ii) संदर्भ के बिंदु (iii) विधान। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 19566 की धारा 3

(ब) समर्थन की विशेषता है। यह खंड कहता है, "समर्थन में (I) सभी मामलों में, भोजन, कपड़े, घर, स्कूली शिक्षा और नैदानिक भागीदारी और उपचार की व्यवस्था, (ii) एक अविवाहित छोटी लड़की के कारण, उसकी शादी के लिए एक प्रकरण की समझदार लागत शामिल है ,

(स) "नाबालिग" एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।" हरियाणा राज्य बनाम श्रीमती में। यह माना गया कि यह हिंदू विधि द्वारा बनाई गई जिम्मेदारी है और सभाओं के न्यायिक संबंध से निकलती है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956, की धारा 18 का उद्देश्य भरण–पोषण और पत्नी के घर को अलग करना है।

अंतरिम भरण–पोषण का अधिकार

अंतरिम भरण–पोषण अनुरोध के प्रदर्शन की तारीख से वाद के छूटने की तारीख तक या सॉलिसिटरों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने की घोषणा के पारित होने तक देय है। पुरुषोत्तम महाकुद बनाम श्रीमती। अन्नपूर्णा महाकुद8, उच्च न्यायालय ने माना कि एक सूट में अंतराल भरण–पोषण की गारंटी का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत काफी अधिकार है। यद्यपि उक्त अधिकार को बनाए रखने के लिए किसी विधि का समर्थन नहीं किया गया है, एक दीवानी अदालत अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतरिम भरण–पोषण की अनुमति दे सकती है।

भरण–पोषण पेंडेंट लाइट

भरण–पोषण पेंडेंट लाइट का अर्थ है मामले के परिणाम पर निर्भर होना। मानक बाद में मामला बातचीत के दौरान पति या पत्नी की मौद्रिक स्थिति पर विचार कर रहा है; पत्नी को मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट दी जाती है, इस बात के बावजूद कि मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट के पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करने में कोई पूर्व निर्धारित व्यवस्था नहीं है।

महिला से अलग रहन–सहन की गारंटी उतनी ही दे सकती है, जितनी वह जीवनसाथी के साथ इस स्थिति में हिस्सा लेती रहती है। जो उससे अलग हो गया है, उसके पति या पत्नी का उसके साथ भरण–पोषण करने का कानूनी दायित्व है, यदि वह स्वयं के साथ भरण–पोषण नहीं कर सकती है और वह अविवाहित रहती है।

पति के साथ भरण–पोषण की प्रतिबद्धता पति पर रहती है, भले ही पत्नी अलग रह रही हो। यह तय किया गया विधि है कि एक अदालत पर्याप्त मदद की अनुमति देने में सक्षम है, इसे अंतराल के आधार पर देने में कुशल है, भले ही इसे देने के प्रस्ताव में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।

विधवा के लिए भरण–पोषण

जीवनसाथी की स्वतंत्र संपत्ति पर विधवा का कोई शुल्क नहीं है। न तो पति या पत्नी के भरण–पोषण से जुड़ी धारा 18 और न ही विधवा के प्रबंधन की धारा 21 में पति या पत्नी की अलग–थलग संपत्ति पर भरण–पोषण के लिए कोई शुल्क शामिल है।

वैकल्पिक आवास/अलग आवास का अधिकार

पति या पत्नी को भरण–पोषण के अधिकार को लहराए बिना अलग रहने का अधिकार है यदि उसका पति परित्याग का दोषी है, यदि वह अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है यदि पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, यदि उसकी कोई अन्य पत्नी जीवित है, तो घर में एक उपपत्नी रखता है। वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, अगर वह हिंदू नहीं रह गया है, या यदि कोई अन्य कारण है जो उसे हमा की धारा 18 (2) के तहत अलग रहने का औचित्य देता है।

पति या पत्नी अकेले रह रहे थे, और हर एक युवा को उसके द्वारा बिना किसी मदद और मदद के पाला गया था, और त्याग का एक उचित उदाहरण था; पत्नी स्वतंत्र घर और भरण–पोषण के लिए योग्य थी। एक पति या पत्नी द्वारा भरण–पोषण के मामले को भी प्रावधान (जी) के तहत समर्थन दिया जा सकता है, यहां तक कि एक या अलग–अलग बयानों से आच्छादित आधार पर भी, उदाहरण के लिए, धारा 18(2) के प्रावधान (ए) से (एफ) को पर्याप्त रूप से लेकिन पूरी तरह से नहीं। केवल इसलिए कि पत्नी विशिष्ट आधारों को कड़ाई से साबित करने में विफल रहती है, उसे उक्त कृत्यों के तहत राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है।

राजेश बनाम नेहा सुप्रीम कोर्ट ने डी.वी. अधिनियम में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट आलिया के गर्भ में एक गृह अनुरोध पारित कर सकता है, जो प्रतिवादी को उसी तरह की वैकल्पिक सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जैसा कि साझा परिवार में उसके द्वारा आनंदित महिला के लिए समान स्तर की सुविधा प्राप्त करने के लिए। इस तरह के अनुरोध को पारित करते समय, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को सभाओं की वित्तीय आवश्यकताओं और संपत्ति का सम्मान करते हुए पट्टा और अन्य किश्तों का भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

विधवा बहू को भरण पोषण

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम की धारा 19 बताती है कि एक विधवा बहू अपने ससुर द्वारा भरण–पोषण की हकदार है। राज किशोर मिश्रा बनाम मीना मिश्रा14 में यह माना गया कि जहां बहू माता–पिता की संपत्ति से अपना भरण–पोषण कर सकती है, वहां ससुर का सवाल ही नहीं उठता। हमा की धारा 20 हिंदू परिवार के मुखिया को बच्चों और वृद्धों और बूढ़े माता–पिता का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य करती है। यहां पिता और माता का भी पालन–पोषण करना अनिवार्य है। हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम की धारा 22 हिंदू परिवार के मुखिया को अपने प्रतिवादियों को बनाए रखने के लिए बाध्य करती है, जिसे धारा 21 के तहत परिभाषित किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत उद्देश्य एक व्यक्ति को इस ईमानदार विश्वास को निभाने के लिए बाध्य करता है कि वह अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता–पिता के संबंध में आम जनता के प्रति एक गंभीर दायित्व से मजबूर है। दायित्व लंबे समय तक वैध और व्यक्ति पर सीमित है। दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 के प्रावधान प्रकृति में प्रचलित, सहज और सर्वव्यापी हैं और धर्म, प्रतिष्ठा और विश्वास की परवाह किए बिना भारत में सभी नेटवर्क के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 125 का उद्देश्य, दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973, कुछ भी लागू करने योग्य है जो व्यक्तिगत विधि हो सकता है जिसके माध्यम से संबंधित विशेष लोगों को निर्देशित और प्रशासित किया जाता है। ऐसे निजी कानूनों के तहत विभिन्न विश्वासों और प्रक्रियाओं का पालन करने वाले व्यक्तियों के विशेष व्यक्तिगत कानूनों के तहत भरण–पोषण पर जोर दिया जा सकता है, फिर भी दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 के तहत बताई गई प्रक्रियाएं किसी भी मामले में संक्षिप्त हैं और स्थिति, सिद्धांत पर थोड़ा ध्यान देने वाले सभी पर लागू होती हैं। धर्म एक आवश्यक, तीव्र और सम्मोहक प्रतिबंधित उपशमन के माध्यम से, दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 के लिए याद की गई व्यवस्था, बर्खास्त पति या पत्नी, माता–पिता और बच्चों (नाबालिग) को पूर्ण गरीबी से भी दूर करने का प्रयास करती है। दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 भुखमरी और सामान्य विनाश के खिलाफ तेजी से इलाज देती है। इसकी तुलना जीवनसाथी के सामान्य दायित्व से नहीं की जाती है। यह एक रूपरेखा रणनीति का समर्थन करता है जिसमें बहुत सारी पेचीदगियां नहीं होती हैं।

यह एक पुरुष व्यक्ति के महत्वपूर्ण दायित्व को प्रभावित करता है कि वह अपने महत्वपूर्ण अन्य, बच्चों और परिपक्व प्रबुद्ध अभिभावकों के साथ खुद को कोई भुगतान नहीं करता है। दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण–पोषण की जगह के पीछे आवश्यक विचार यह है कि कोई भी पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे, बूढ़े अभिभावक बिना जरूरत के तनाव में न हों और इस लक्ष्य के साथ पूरी तरह से तनाव में

न आएं कि उन्हें उल्लंघन का जवाब लेने के लिए लुभाने की आवश्यकता हो, और इसी तरह दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 के तहत व्यवस्था प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट को आवश्यकता की प्रत्याशा के लिए रूपरेखा गतिविधि लेने की मंजूरी देती है।

3. भारतीय विधि और उद्देश्य और भरण–पोषण का दायरा

शब्द "भरण–पोषण" को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा IX में परिभाषित या परिभाषित नहीं किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय IX की धारा 125 के तहत उद्देश्य नागरिक अधिकारों का समर्थन करता है, जिसे महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए असाधारण रूप से स्वीकृत किया गया था, इसलिए वृद्धों के साथ–साथ अभिभावक भी कमजोर थे। भरण–पोषण का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और उसके अनुच्छेद 39 के दायरे में आता है। धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 बताता है कि किसी व्यक्ति का यह महत्वपूर्ण और नियमित दायित्व है कि वह अपने जीवनसाथी, बच्चों और वृद्ध अभिभावकों के साथ तब तक भरण–पोषण करे जब तक कि वे उनके साथ भरण–पोषण नहीं कर सकते।

धारा 125 का उद्देश्य, दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 लागू होते हैं और किसी भी चीज से स्वतंत्र होने के लिए अधिकृत होते हैं जो कि व्यक्तिगत विधि हो सकता है जिसके द्वारा भारत में लोगों को प्रशासित किया जाता है। हर समय, यह माना जाना चाहिए कि संबंधित सभाओं के व्यक्तिगत कानूनों, हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों के बारे में उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि विवाह बंधन की वैधता को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, यदि कोई हो, (मौजूद है या नहीं) इस प्रकार उचित विचार से बचाया नहीं जा सकता।

धारा 125, दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 के पीछे का उद्देश्य 1973, भुखमरी से बचने पर केंद्रित है, परिवार के सदस्यों की हताशा भी आवारा, करीबी और दूर, यानी प्रतिवादी जो अपने साथ नहीं रख सकते। यह महिलाओं, युवाओं और वृद्ध अभिभावकों को सुनिश्चित करने के लिए असाधारण रूप से आदेशित नागरिक अधिकारों का अनुपात है। धारा 125 का मुख्य उद्देश्य, दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973, परित्यक्त पति–पत्नी, उपेक्षित और उपेक्षित युवाओं और कमजोर, वृद्ध, दुर्बल अभिभावकों को राहत देने के लिए है। इस तरह की यह व्यवस्था समृद्धि के पीछे सामाजिक सहायता और सामाजिक प्रेरणा लाती है। मजिस्ट्रेट का वार्ड सुधारात्मक या सुधारात्मक नहीं है, स्पष्ट रूप से निवारक प्रकृति का है। एक सीधी, तेज, प्रतिबंधित सहायता देकर, सामान्य विधि और मुकदमे के थकाऊ, व्यापक, चिड़चिड़े, वजनदार चक्र को आवेग से दूर रखने की कोशिश की गई (कुछ हद तक) उन लोगों पर मजबूर किया जाता है जिनका दायित्व अपने प्रतिवादियों के साथ बनाए रखना है जो कर सकते हैं अपने साथ नहीं रखते। किसी भी पति या पत्नी, बच्चे या माता–पिता को भिखारी और दरिद्र नहीं छोड़ा जा सकता है ताकि वे गलत काम करने के लिए या दूसरों को उनके बारे में गलत काम करने के लिए लुभा सकें। अपने स्वयं के बेहतर आधे के साथ बनाए रखने का दायित्व और नाबालिग बच्चे एक कानूनी प्रतिबद्धता है, और अधिकार को पूरी तरह से त्यागने के बराबर के विरोध में एक अनुबंध को वैध नहीं माना जा सकता है. भारत में विभिन्न नेटवर्कों के बीच भरण–पोषण कानूनों को विशिष्ट रूप से व्यक्तियों के अधिक नाजुक वर्गों को सुरक्षित करने के लिए स्वीकृत किया गया है, उदाहरण के लिए, महिलाओं, युवाओं, बूढ़े और कमजोर अभिभावकों को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ करीबी रिश्ते जिनके पास स्वयं का कोई भुगतान नहीं है और नहीं कर सकते हैं अपने व्यवसाय के साथ बनाए रखें। इसी तरह, यह असाधारण रूप से व्यक्त किया जा सकता है कि भरण–पोषण विधि 15(3), 24 के अनुच्छेद 11 के संरक्षित दायरे में आते हैं। भरण–पोषण के प्रावधानों को आम तौर पर भारत के संविधान के समान पाया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं है।

इन प्रावधानों की योजना एक सामाजिक कारण की गारंटी के लिए बनाई गई है। उनका लेख एक आदमी को नैतिक बाधाओं को करने के लिए मजबूर करना है, जो वह अपने महत्वपूर्ण अन्य, युवाओं, अभिभावकों के बारे में खुले तौर पर आम जनता के लिए है। एक सीधी, तेज, प्रतिबंधित उपशमन उत्पन्न करके, ये प्रावधान इस बात की गारंटी देते हैं कि उपेक्षित असहाय पति–पत्नी और बच्चे समाज के कूड़े के ढेर पर गरीब और दरिद्र न बनें और इस तरह आवारापन, उल्लंघन के अस्तित्व के लिए विवश हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके सरल साधनों के लिए भ्रष्टाचार। जीवनसाथी, नौजवान, माता या पिता की खुद को बनाए रखने की अपर्याप्तता असाधारण महानता के वास्तविक सामाजिक मुद्दों को जन्म दे सकती है। इस तरह के विचार और एकीकृत मामलों में, संसद को इस मुद्दे के लिए एक उत्तर तैयार करने की आवश्यकता थी और इसके परिणामस्वरूप एक सारांश पद्धति विकसित हुई जिसे नई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अपना स्थान और विस्तार मिला।

4. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956 और दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 1973 के तहत भरण–पोषण कानूनों के बीच तुलना

दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 के तहत बनाए रखने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जिसे भारतीय शासी निकाय ने संबंधित सभा के किसी भी धर्म से स्वतंत्र माना है, स्वीकार किया है और माना है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम और इसी तरह की धाराओं के प्रावधान हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के 18 और 20 केवल हिंदुओं के लिए ही उपयुक्त हैं।

धारा 125 दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 का उद्देश्य एक सामाजिक कारण के लिए एक सिनॉप्सिस मशीन देना है जो एक आदमी की नैतिक बाधा को उसके महत्वपूर्ण अन्य, बच्चों और बूढ़े अभिभावकों को पूरा करने के लिए प्रदान करता है ताकि वे पूर्ण विनाश के कारण धूल को न काट सकें क्योंकि वे खुद के साथ नहीं रह सकते हैं। इस भाग का उद्देश्य एक व्यवस्थित समाज के हितों की रक्षा करना है। हिंदू दत्तक

ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधान हिंदू व्यक्तिगत विधि के तहत हिंदू पति–पत्नी, युवाओं और बूढ़े और कमजोर अभिभावकों या यहां तक कि बच्चों को रखने की स्वतंत्रता देते हैं।

सुझाव

1. भारत में अनगिनत ऐसे नेटवर्क के बीच भारत में अलग–अलग भरण–पोषण विधि हैं। वास्तविक मुद्दा यह है कि भारत के माध्यम से एक समान छतरी के नीचे भरण–पोषण के समान कानूनों के प्रस्ताव और विचार कैसे हो सकते हैं और जिन्हें अधिक राज्यों में रोल मॉडल के रूप में कार्य करना चाहिए। भारत में भारतीय आबादी के मध्य भाग में हिंदू और मुसलमान शामिल हैं। उन दोनों में भरण–पोषण के विधि हैं। दोनों शास्त्री और आधुनिक हैं।
2. भारत में उपलब्ध कानूनों के बावजूद, आवेदन पर निर्णय लेने के लिए किसी भी अधिनियम में कोई सीमा निर्धारित नहीं है, और न ही अदालतें इस पर सख्ती से निपटती हैं जिसके कारण पत्नी और बच्चों को पीड़ित होना पड़ता है।
3. दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 के तहत, एक मजिस्ट्रेट के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के क्षेत्र धारा 151 या दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 482 जैसी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं होती है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय को जन्मजात शक्ति प्राप्त होती है। सेक के तहत दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 के धारा 362, मजिस्ट्रेट अपने आदेश को समायोजित या सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं।

निष्कर्ष

हिंदू स्थानीय क्षेत्र के समर्थन कानूनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और उचित जांच करके, उपलब्ध संसाधनों की खोज के लिए सफल उपाय किए जाने चाहिए कि कैसे समर्थन कानूनों में खामियों, छिद्रों, विषमताओं को नष्ट किया जाए। उसे यह पता लगाना होगा कि भारत में एकसमान रख–रखाव कानूनों के संबंध में विचारों की खोज कैसे की जा सकती है; इस प्रकार, यदि हर चीज में, यह व्यावहारिक रूप से यह मानने की प्रवृत्ति रखता है कि यह मामला है, तो किस सकारात्मक तरीके से, समर्थन कानूनों की स्थिरता और स्थिरता लाने के लिए। लगभग निश्चित रूप से, भारत की संसद महत्वपूर्ण नियम ला सकती है; हालांकि, नियामक महान शुभकामनाएं होनी चाहिए। इस आकर्षण में तेजी से अधिक कानूनी सक्रियता खुशी से प्राप्त हो सकती है। भारत में प्रसिद्ध कानूनी सलाहकारों का एक पैनल निरंतरता की सिफारिश करने और खामियों, विसंगतियों, खामियों और खामियों को दूर करने के लिए संसद की मदद कर सकता है।

संदर्भ

[1] ए. आई. आर. 2005 एससी 1809
[2] नानक चंद बनाम चंद्र किशोर, ए. आई. आर. 1970 एससी 446
[3] यमुनाबाई बनाम अनंत राव, ए. आई. आर. 1988 एससी 644।
[4] बृहस्पति, XV.
[5] ए. आई. आर. 1997 ओरि 73.
[6] रोहताश सिंह बनाम श्रीमती रामेंद्री, ए. आई. आर. 2000 एससी 1952।
[7] मीरा निरेश्वलिया बनाम सुकुमार निरेश्वलिया, ए. आई. आर. 1994 मैड 168.
[8] साधु सिंह बनाम गुरुद्वारा साहिब नारिके, ए. आई. आर. 2006 एससी 3282।
[9] मीरा निरेश्वलिया बनाम सुकुमार निरेश्वलिया, ए. आई. आर. 1994 मैड 168.
[10] रजनीश बनाम नेहा सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपील सं। 2020 का 730
[11] ए. आई. आर. 1995 सभी 70.
[12] यहां दंड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 125 "(1) यदि पर्याप्त साधन छोड़ने वाला कोई व्यक्ति उपेक्षा करता है या रखरखाव करने से इनकार करता है– (ए) उसकी पत्नी, खुद को बनाए रखने में असमर्थ, या (बी) उसकी वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, चाहे विवाहित हो या नहीं, अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हो, या (सी) उसका वैध या नाजायज बच्चा (विवाहित बेटी न हो) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, जहां ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण करने में असमर्थ हो खुद को बनाए रखना या, (डी) उसके पिता या मां, खुद को या खुद को बनाए रखने में असमर्थ।
[13] भगवान दत्त बनाम कमल देवी, (1975) 2 एस.सी.सी. 386.
[14] नानक चंद बनाम चंद्र किशोर, ए. आई. आर. 1970 एससी 446
[15] मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, ए आई आर 1985 एससी 945।
[16] बद्री नारायण बनाम लक्ष्मी गहलोत, 2002 एस.सी.सी. ऑनलाइन राज 2009।
[17] यमुनाबाई बनाम अनंत राव, ए. आई. आर. 1988 एससी 644।
[18] विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट, 303.
[19] हारून बनाम सैनभा बीवी ज़ीनाथ, ए.आई.आर. 1994 एससी 1456।
[20] रमेश चंद्र बनाम वीणा कौशल, ए. आई. आर. 1987 एससी 1807।